



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 60-2018/Ext.]

चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 11 अप्रैल, 2018
(21 चैत्र, 1940 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	1. अधिसूचना संख्या का0आ022/ह0अ034/2017/धा046/2018, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 — गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकार तथा दायित्व) हस्तान्तरण योजना, 2018.	257-267
	2. अधिसूचना संख्या का0आ023/ह0अ034/2017/धा045/2018, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 — गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सम्पत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकार तथा दायित्व) हस्तान्तरण योजना, 2018. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	269-415
भाग IV	शुद्धि-पर्वी, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग—III**हरियाणा सरकार**

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 अप्रैल, 2018

संख्या का0आ0 22/ह0अ034/2017/धा046/2018. गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 (2017 का 34), की धारा 46 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, आन्तरिक विकास कार्यों से अन्यथा, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 के अधीन स्थापित प्राधिकरण को अवसंरचना विकास कार्यों के सम्बन्ध में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम की संपत्तियों, संपत्तियों में हित, अधिकारों और दायित्वों के हस्तान्तरण, इस हस्तान्तरण योजना के निबन्धनों के अनुसार, को उपबन्धित करने तथा प्रभावी रूप देने के लिए तथा उससे आनुषांगिक तथा प्रासंगिक मामलों के लिए निम्नलिखित हस्तान्तरण योजना बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) यह योजना गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम संपत्ति, सम्पत्ति में हित, अधिकार तथा दायित्व) हस्तान्तरण योजना, 2018, संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। कही जा सकती है।

(2) इस योजना का विस्तार गुरुग्राम महानगर क्षेत्र में तथा आगे हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम की सभी संपत्तियों, संपत्तियों के हितों, अधिकारों और दायित्वों की सीमा तक होगा, जो हरियाणा राज्य के भीतर और बाहर अब स्थित हैं, जहां तक हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम की ऐसी सम्पत्तियों, सम्पत्तियों में हित, अधिकार तथा दायित्व, गुरुग्राम महानगर क्षेत्र में स्थित आन्तरिक विकास कार्यों से अन्यथा अवसंरचना विकास कार्यों से सम्बन्धित हैं।

(3) हस्तान्तरण योजना प्रथम अप्रैल, 2018 से लागू होगी;

2. (1) इस हस्तान्तरण योजना में, विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

(क) “अधिनियम” से अभिप्राय है, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 (2017 का 34) ;

(ख) “आस्तियों” से अभिप्राय है, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित अन्य आन्तरिक विकास कार्यों से भिन्न, अवसंरचना विकास कार्यों से सम्बन्धित हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम की सभी संपत्तियों और सम्पत्तियों में हित, चल तथा अचल, इसमें सड़कों, जलापूर्ति प्रणालियों तथा पाईपलाइनों, निकास व्यवस्था (सीवरेज सिस्टम) सहित और पाईपलाइनों, वर्षा जल निकासी प्रणालियों तथा पाईपलाइनों, सड़कों के साथ-साथ हरित क्षेत्र, निर्दिष्ट उद्यानों, इमारतों, पौधों, मशीनरी, दुकानों, कार्यशालाओं और प्रतिष्ठानों से जुड़े हरित स्थान, मूर्त और अमूर्त संपत्ति, रास्ते, लाभ, अनुज्ञप्ति, सहमति, प्राधिकार, हर तरह की प्रकृति और विवरण, विधेयाधिकार, स्वतंत्रता, हित, लाभ तथा अनुमोदन, संविदा विलेख, स्कीमों, बन्ध-पत्रों, समझौतों और अन्य साधनों और ब्याज (प्राप्य सहित) की प्रकृति और जहां कहीं भी स्थित है, का पंजीकरण और शक्तियों भी शामिल हैं ;

(ग) “प्रभावी तिथि” से अभिप्राय है, प्रथम अप्रैल, 2018 है;

(घ) “दायित्वों” में शामिल है सभी देनदारियां, ऋण, कर्तव्य, बाध्यता तथा अन्य बकाया देयताएं शामिल है जिसमें वैधानिक दायित्व तथा सरकारी उद्ग्रहण, जो किसी भी स्वरूप तथा सम्भाव्य दायित्व के हों भी शामिल हैं जो गुरुग्राम महानगर क्षेत्र में स्थित आन्तरिक विकास कार्यों से भिन्न हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के अवसंरचना विकास कार्यों के सम्बन्ध में प्रभावी तिथि से पहले के व्यवहार के सम्बन्ध में उत्पन्न हो सकती हैं;

(ड) “कार्यवाहियों” में वादों, अपीलों, शिकायतों, याचिकाओं, आवेदनों, सुलह, माध्यस्थमों, दीवानी अथवा आपराधिक मामले या अन्यथा, जिनमें हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम पक्षकारों के रूप में है, सहित सभी प्रकार की कार्यवाहियां शामिल हैं;

(च) “अनुसूची” से अभिप्राय है, इस हस्तान्तरण योजना से संलग्न अनुसूची

(2) इस हस्तान्तरण योजना में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में दिए गए हैं।

हरियाणा राज्य
औद्योगिक एवं
अवसंरचना विकास
निगम की
संपत्तियों का
वर्गीकरण ।

3. (1) हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम की संपत्तियों को अनुसूचियों में निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है :-

(क) अनुसूची क में वर्णित अवसंरचना विकास कार्य;

(ख) अनुसूची ख में वर्णित भवन

(2) यदि उक्त खंड 3 के उपखंड (1) के अधीन सम्पत्तियां किन्हीं उधारों या व्यवस्थाओं के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा ली गई किसी वित्तीय सहायता या दायित्वों के लिए किसी तृतीय पक्षकार के पक्ष में प्रतिभूति के अध्वधीन हैं और उसके संबंध में दायित्व हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम तथा प्राधिकरण में वर्गीकृत किए जाने हैं, तो राज्य सरकार, उक्त प्रयोजन के लिए जारी किये जाने वाले आदेश द्वारा, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम और प्राधिकरण के बीच ऐसी संपत्तियों, परिसंपत्तियों और अधिकारों द्वारा सुनिश्चित दायित्वों का विभाजन कर सकती है और इस तरह के विभाजन पर प्रतिभूति केवल विभाजित दायित्व की सीमा तक लागू होगी।

हस्तान्तरण का
प्रभाव ।

4. (1) प्रभावी तिथि को या से और अधिनियम तथा इस हस्तान्तरण योजना में निर्दिष्ट निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, आस्तियों और दायित्वों, कार्यवाही और अभिलेख, चाहे भौतिक या डिजिटल, जो अनुसूची क और ख के रूप हैं, राज्य सरकार या हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम या किसी भी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली किसी आगामी कार्यवाही या बात के बिना सभी उद्देश्यों तथा प्रयोजनों के लिए पूर्ण रूप से प्राधिकरण में हस्तान्तरित तथा निहित हो जायेंगे।

(2) ऐसे हस्तान्तरण पर, प्राधिकरण प्रभावी तिथि से हस्तान्तरित की गई संपत्तियों अथवा उसके संचालनों तथा उनके रखरखाव से संबंधी या उत्पन्न सभी प्रकार के कृत्यों, कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों तथा दायित्वों का निर्वहन करेगा।

(3) ऐसे हस्तान्तरण पर तथा प्रभावी तिथि से, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के ऋण, परिदान, बाध्यताएं समाप्त तथा रद्द हो जाएंगी जो इस हस्तान्तरण योजना या किसी अन्य अधिसूचना, जो राज्य सरकार द्वारा जारी की जाए, में वर्णित के सिवाय, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के सभी दावों का पूर्ण तथा अंतिम निपटान होगा।

(4) ऐसे हस्तान्तरण के होने पर तथा इसके बाद उपरोक्त उपबंधित कृत्यों के निहित होने पर तथा यथा उपबंधित से अन्यथा के सिवाय, प्राधिकरण, इसे हस्तान्तरित की गई सम्पत्तियों, चाहे किसी स्वरूप की हों, के सम्बन्ध में सभी कृत्यों, सविदाओं, अधिकारों, विलेखों, योजनाओं, बन्धपत्रों, करारों, व्यवस्थाओं, कार्यवाहियों तथा अन्य लिखतों के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम पक्षकार था और जो प्रभावी तिथि को अस्तित्व में या प्रभावी है, और उसी रीति में दायी होगा, जैसे हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम प्रभावी तिथि से ठीक पहले दायी थी, और वे प्राधिकरण के विरुद्ध लागू तथा प्रभावी होंगे, और वे ऐसे रूप में लागू किये जा सकते हैं मानो प्राधिकरण हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के बजाय पक्षकार था।

(5) उपर्युक्त इस खण्ड की कोई भी बात, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के कर्मचारियों और अन्य कार्मिकों के सम्बन्ध में अधिकारों, जिम्मेदारियों, दायित्वों और बाध्यताओं तथा वैधानिक देयों जैसे वेतन, मजदूरी, उपदान, पेंशन, भविष्य निधि, छुट्टी नकदीकरण/चिकित्सा लाभ, क्षतिपूर्ति तथा सेवानिवृत्ति लाभों सहित हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के कर्मचारियों और अन्य कार्मिकों से सम्बन्धित मामलों को लागू नहीं होगी।

(6) इस हस्तान्तरण योजना में यथा विनिर्दिष्ट हस्तान्तरण और निहित प्रतिफल, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम से प्राधिकरण को हस्तान्तरित किए गए तुलनपत्र तथा वित्तीय मामलों को अधिसूचित करेगी ।

(7) राज्य सरकार, इस प्रयोजनार्थ जारी किए जाने वाले आदेश द्वारा, इस हस्तान्तरण योजना के खण्ड 7 में वर्णित अनन्तिम अवधि के दौरान किसी भी समय अनुसूचियों में निर्दिष्ट निबन्धनों तथा शर्तों को संशोधित, बदल, उपान्तरित, जोड़, लोप या अन्यथा परिवर्तित कर सकती है ।

(8) प्राधिकरण को हस्तान्तरित संपत्तियों में अधिकार या संपत्तियों में हित, इस हस्तान्तरण योजना या लागू अनुसूची में निर्दिष्ट निबन्धनों और सीमाओं के अनुसार लागू होंगे ।

(9) हस्तान्तरण योजना में किसी बात के होते हुए भी, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, गुरुग्राम महानगर क्षेत्र में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के स्वामित्व, प्रबन्धन और नियंत्रण के अधीन सड़कों के संबंध में अवसंरचना विकास कार्यों के लिए प्राधिकरण को रास्ते तक पहुँच प्रदान करेगा ।

5. अधिनियम और इस हस्तान्तरण योजना के अनुसार हस्तान्तरण के प्रभावी होने पर, सभी व्यक्तियों के अधिकारों और बाध्यताओं को प्राधिकरण तक सीमित किया जाएगा, जिनके अधिकारों, संपत्तियों, संपत्तियों में हित या दायित्वों को सौंपा गया हो और किसी विलेख, दस्तावेज, लिखत, करार या व्यवस्था, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के साथ की गई है, में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा व्यक्ति हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के विरुद्ध किसी भी हक या हित का दावा नहीं करेगा ।

तृतीय पक्षकारों के अधिकार तथा बाध्यताएं ।

6. (1) प्रभावी तिथि पर हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा या के विरुद्ध लम्बित सभी कार्यवाहियों, किसी भी स्वरूप की हों, हस्तान्तरण योजना के अधीन हस्तान्तरण के कारण किसी भी तरह से समाप्त या बन्द या अन्यथा से प्रतिकूल रूप से प्रभावी नहीं होगी और कार्यवाहियों प्राधिकरण द्वारा या के विरुद्ध जारी रहेंगी, अभियोजित या लागू की जाएंगी, जो उसे इस हस्तान्तरण योजना और इसके अधीन जारी किए गए आदेशों के अनुसार सौंपी गई हैं ।

लम्बित वाद, कार्यवाही आदि ।

(2) उपरोक्त उपखंड (1) के अधीन की गई कार्यवाहियों उसी रीति में और उसी सीमा तक जारी रहेंगी, जो हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा या के विरुद्ध जारी, अभियोजित और लागू होती या हो सकती थी, यदि इस हस्तान्तरण योजना में निर्दिष्ट हस्तान्तरण नहीं किया गया होता ।

7. (1) इस हस्तान्तरण योजना के अधीन हस्तान्तरण, जब तक राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश में अन्यथा से विनिर्दिष्ट न हो, प्रभावी तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए अनन्तिम होगा ।

प्रथम दृष्टान्त अन्तिम रूप में संपत्तियों, अधिकारों, आस्तियों, देनदारियों और कार्यवाहियों का वर्गीकरण और हस्तान्तरण ।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचित आदेश द्वारा, प्रभावी तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय, हस्तान्तरण में शामिल मदों सहित हस्तान्तरण के निबन्धनों तथा शर्तों को संशोधित, बदल, उपान्तरित, जोड़, कम, लोप या अन्यथा परिवर्तित कर सकती है, और ऐसी रीति में तथा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो राज्य सरकार उचित समझे, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम की ऐसी आस्तियों, दायित्वों, कार्यवाहियों, अधिकारों तथा बाध्यताओं और उसके भाग का हस्तान्तरण प्राधिकरण या विषयपत्र कर सकती है ।

(3) प्रभावी तिथि से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति पर और राज्य सरकार द्वारा दिए गए किसी निर्देश के अधीन, इस हस्तान्तरण योजना के अनुसार आस्तियों, दायित्वों, कार्यवाहियों, अधिकारों और बाध्यताओं का किया गया हस्तान्तरण अन्तिम होगा ।

8. इस हस्तान्तरण योजना के अधीन हस्तान्तरण, हस्तान्तरण योजना को अधिसूचित करते हुए और इस हस्तान्तरण योजना के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार जारी आदेशों और इस हस्तान्तरण योजना के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार अध्याधीन राज्य सरकार, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम, अन्तरिति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आगे किए जाने वाला कोई कार्य, विलेख या किसी बात के बिना राज्य सरकार की कार्यवाही के अनुसरण में परिचालित तथा प्रभावी होगा ।

विधि के परिचालन द्वारा हस्तान्तरण ।

राज्य सरकार का
निर्णय अंतिम होना ।

9. (1) इस हस्तान्तरण योजना के अधीन हस्तान्तरण के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई संदेह, विवाद या भिन्नता का मुद्दा, अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में आदेश अधिसूचित करते हुए, अधिनियम के उपबन्धों से अनसंगत, इस हस्तान्तरण योजना में संशोधन कर सकती है और ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इस हस्तान्तरण योजना के अधीन हस्तान्तरणों के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

अनुसूची क

{देखिए खंड 3 का उप-खण्ड (1) का मद (क)}

अवसंरचना विकास कार्य—सड़क नेटवर्क (हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम)

सम्पत्ति संख्या 119 शंकर चौक, एनएच-8 से पुराना दिल्ली रोड, डुण्डाहेडा
लम्बाई 1545 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर

सम्पत्ति संख्या 120 एनएच-8 से पुराना दिल्ली रोड, उद्योग विहार रोड
लम्बाई 2078 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर

सम्पत्ति संख्या 121 एनएच-8 से टोल गेट से कापसहेडा बॉर्डर, उद्योग विहार
लम्बाई 2078 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर

अवसंरचना विकास कार्य—पानी सप्लाई तंत्र

क्रम संख्या	सम्पत्ति पहचान संख्या	विवरण	लम्बाई मीटर	व्यास (एमएम)
1	3142	मुख्य लाईन बसई से हरसरु	3187	600
2	3144	मुख्य लाईन हरसरु से सैक्टर एम 7	9000	600

अवसंरचना विकास कार्य— प्रशोधित उत्प्रवाही नाला, सीवर एवं बरसात

क्रम संख्या	सम्पत्ति पहचान संख्या	विवरण	लम्बाई मीटर	माप (मीटर)
1	3167	प्रशोधित उत्प्रवाही नाला सैक्टर एम 15 से पटौदी रोड	8450	6X1.65
2	3168	प्रशोधित उत्प्रवाही नाला पटौदी रोड से बादशाहपुर नाला	2250	7X1.65

अनुसूची ख

[देखिए खंड 3 का उप-खण्ड (1) का मद (ख)]

अवसंरचना विकास कार्य—सड़क नेटवर्क (हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम)

क्रम संख्या	सैक्टर	विवरण	खाली जमीन	जमीन का कुल क्षेत्र
1	99	मुख्य पंपिंग स्टेशन कच्चा पानी बसई	1 नग	6.50 एकड
2		मध्यवर्ती पंपिंग स्टेशन कच्चा पानी हरसरू	1 नग	6.00 एकड
3	एम-7	जल उपचार संयंत्र (आईएमटी मानेसर) मशीनरी सहित 1. तेज संशोधन यंत्र 250 लाख लीटर प्रति दिन 2. धीमा संशोधन यंत्र 100 लाख लीटर प्रति दिन	1 नग	17.00 एकड
4	एम 15 / 16	आम प्रवाह उपचार संयंत्र 1. 250 लाख लीटर प्रतिदिन 2. 300 लाख लीटर प्रतिदिन	1 नग 1 नग	19.00 एकड 8.00 एकड

अरुण कुमार गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

*[Authorised English Translation]***HARYANA GOVERNMENT****TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT****Notification**

The 11th April, 2018

No. S.O.22/H.A.34/2017/S.46/2018.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 46 of the Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017 (34 of 2017), the Governor of Haryana hereby makes the following transfer scheme for providing and giving effect to the transfer of the properties, interests in properties, rights and liabilities of the **Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation** in respect of infrastructure development works, other than internal development works to Authority established under the Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017, as per and in accordance with the terms of this transfer scheme and for matters incidental and ancillary thereto, namely :-

1. (1) This transfer scheme may be called as the Gurugram Metropolitan Development Authority (Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation Properties, interests in Properties, Rights and Liabilities) transfer scheme, 2018. Short title, extent and commencement.

(2) This transfer scheme shall extend to the Gurugram Metropolitan Area and shall, further, extend to all properties, interests in properties, rights and liabilities of the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation that are located both within and outside the State of Haryana, in so far as such properties, interests in properties, rights and liabilities of Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation, are related to infrastructure development works, other than internal development works, located in the Gurugram Metropolitan Area.

(3) This transfer scheme shall come into force on the 1st April, 2018.

2. (1) In this transfer scheme, unless there is anything repugnant in the subject or context, Definitions.
namely:-

- (a) “**Act**” means the Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017;
- (b) “**assets**” means all properties and interests in properties, immovable and movable, of Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation relating to infrastructure development works, other than internal development works, located in the Gurugram Metropolitan Area, including roads, water supply systems and pipelines, sewerage systems and pipelines, storm water drainage systems and pipelines, green spaces abutting roads, specified parks, buildings, plants, machinery, stores, workshops, and installations pertaining and attached thereto tangible and intangible assets, right of way, benefits, licenses, consents, authorities, registration and powers of every kind, nature and description whatsoever, privileges, liberties, advantages, benefits and approvals, contracts, deeds, schemes, bonds, agreements and other instruments and interest (including receivables) of whatever nature and wherever situated;
- (c) “**effective Date**” means 1st April, 2018;
- (d) “**liabilities**” include all liabilities, debts, duties, obligations and other outstandings including statutory liabilities and government levies of whatever nature and contingent liabilities which may arise in regard to the dealings before the effective date in respect of infrastructure development works of Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation, other than internal development works, located in the Gurugram Metropolitan Area;
- (e) “**proceedings**” include all proceedings of whatever nature including suits, appeals, complaints, petitions, applications, conciliation, arbitration, whether civil or criminal cases or otherwise, in which the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation is one of the parties;

(f) “**Schedules**” means the schedules appended to this transfer scheme;

(2) Words and expressions used herein and not defined in this transfer scheme but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

Classification of properties of the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation.

3. (1) The properties of the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation are classified in the Schedules as follows :-

- (a) Infrastructure Development Works as set out in Schedule A; and
- (b) Buildings as set out in Schedule B.

(2) If the properties under sub-clause (1) of clause 3 above are subject to security for any borrowings or arrangements in favour of third parties for any financial assistance or obligations taken by the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation and the Liabilities in respect thereof are to be classified in the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation and Authority, the State Government, may by order to be issued for the said purpose, provide for the apportionment of the liabilities secured by such properties, assets and rights between the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation and Authority and upon such apportionment the security shall be applicable to the extent of apportioned liability only.

Effects of transfer.

4. (1) On and from the effective date and subject to the terms and conditions specified in the Act and this transfer scheme, the assets and liabilities, proceedings and records, whether physical or digital, of the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation that form part of Schedules A and B shall stand transferred to and vest in Authority absolutely for all intents and purposes, without any further act or thing to be done by the State Government or the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation or any person.

(2) Upon such transfer, Authority shall, from the effective date, discharge all functions, duties, responsibilities and liabilities with respect to or arising from the transferred properties or the operations and maintenance thereof.

(3) Upon such transfer and with effect from the effective date, the loans, subventions and obligations of Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation shall stand extinguished and cancelled, which shall be in full and final settlement of all claims of Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation except as set out in this transfer scheme or any other notification as may be issued by the State Government.

(4) On such transfer and vesting of the functions provided hereinabove and except as otherwise provided, Authority shall be responsible for all functions, contracts, rights, deeds, schemes, bonds, agreements, arrangements, proceedings and other instruments of whatever nature relating to the properties transferred to it to which the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation was a party, subsisting or having effect on the effective date, and in the same manner as the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation was liable immediately before the effective date, and the same shall remain in force and effect against or in favour of Authority and may be enforced effectively as if Authority had been a party thereto instead of the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation.

(5) Nothing in the clause above shall apply to rights, responsibilities, liabilities and obligations in respect of the employees and other personnel of the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation and matters relating to employees and other personnel of the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation, including statutory dues such as salary, wages, gratuity, pension, provident fund, leave encashment/medical benefits, compensation and retirement benefits.

(6) As consideration for the transfer and vesting as specified in this transfer scheme, the State Government shall, by order, notify the balance sheet and financials deemed to have been transferred from the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation to Authority.

(7) The State Government may, by an order to be issued for the purpose, amend, vary, modify, add, delete or otherwise change the terms and conditions specified in the Schedules at any time during the provisional period mentioned in clause 7 of this transfer scheme.

(8) The rights in the properties or interests in properties transferred to Authority shall be subject to the restrictions and limitations specified in this transfer scheme or in the applicable Schedule.

(9) Notwithstanding anything contained in the transfer scheme, the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation shall provide right of way access to Authority for infrastructure development works in respect of roads under the ownership, management and control of the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation in the Gurugram Metropolitan Area.

5. Upon the transfer being effected in accordance with the Act and this transfer scheme, the rights and obligations of all persons shall be restricted to Authority to whom the rights, properties, interests in properties or liabilities are assigned and notwithstanding anything contained in any deed, documents, instruments, agreements or arrangements which such person has with the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation, the person shall not claim any right or interest against the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation.

Rights and obligations of third party.

6. (1) All proceedings of whatever nature by or against the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation pending on the effective date shall not abate or discontinue or otherwise in any way prejudicially be affected by reason of the transfer under this transfer scheme and the proceedings shall be continued, prosecuted and enforced by or against Authority to whom the same are assigned in accordance with this transfer scheme and orders issued thereunder.

Pending suits, proceedings, etc.

(2) The proceedings covered under sub-clause (1) above shall be continued in the same manner and to the same extent as it would or might have been continued, prosecuted and enforced by or against the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation if the transfer specified in this transfer scheme had not been made.

7. (1) The transfer under this transfer scheme, unless otherwise specified in any order made by the State Government, shall be provisional for a period of one year from the effective date.

Classifications and transfer of property, rights, assets, liabilities and proceedings to be provisional in the first instance.

(2) At any time within a period of one year from the effective date, the State Government may, by notified order publish in the Official Gazette, amend, vary, modify, add, reduce, delete or otherwise change the terms and conditions of the transfer including items included in the transfer, and transfer such of the assets, liabilities, proceedings, rights and obligations and forming part of the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation to Authority or vice versa, in such manner and on such terms and conditions as the State Government may consider appropriate.

(3) On the expiry of the period or one year from the effective date and subject to any directions given by the State Government, the transfer of assets, liabilities, proceedings, rights and obligations made in accordance with this transfer scheme shall become final.

8. The transfer under this transfer scheme shall operate and be effective pursuant to action of the State Government by notifying this transfer scheme and orders issued in terms of this transfer scheme and without any further act, deed or thing to be done by the State Government, the Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation, Transferees or any other person, subject to the terms and conditions of this transfer scheme.

Transfer by operation of law.

9. (1) If any doubt, dispute, difference or issue arises in regard to the transfers under this transfer scheme, then, subject to the transfers under this transfer scheme, then, subject to the provisions of the Act, the decision of the State Government thereon shall be final and binding on all parties.

Decision of State Government to be final.

(2) The State Government may, by order notified in the Official Gazette, amend this transfer scheme and make such provisions, not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulties arising in implementing the transfers under this transfer scheme.

SCHEDULE 'A'*(See item (a) of sub-clause (1) of clause 3)***INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT WORKS- Road Network (Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation)**

Asset ID-119 Shankar Chowk, NH-8 to Old Delhi Road, Dundahera
Nominal L= 1545 M, Row= 30 M

Asset ID-120 NH-8 to Old Delhi Road UdyogVihar Road
Nominal L= 2078 M, Row= 30 M

Asset ID-121 NH-8 Toll gate to Kapashera Border, UdyogVihar
Nominal L= 1350 M, Row= 30 M

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT WORKS- Water Supply Network

Serial Number	Assets ID	Description	Length (Mtr)	Diameter (mm)
1	3142	Rising main Basal to Harsaru	3187	600
2	3144	Rising Main Harsaru to Sector M7	9000	600

INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT WORKS- Treated Effluent Channel Sewer & Storm Water

Serial Number	Assets ID	Description	Length (Mtr)	Size (Mtr)
1	3167	Treated effluent channel M15 to Pataudi Road	8450	6x1.65
2	3168	Treated effluent channel Pataudi Road to Badsahpur drain	2250	7x1.65

SCHEDULE 'B'*(See item (b) of sub-clause (1) of clause 3)***INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT WORKS- Building including structure thereon**

Serial No.	Sector	Name of Site	Vacant Site	Total Area of Land
1	99	Main pumping station (RAW water) Basai	1 No.	6.50 Acre
2	—	Intermediate Pumping station (RAW Water) Harsaru	1 No.	6.00 Acre
3	M7	Water treatment plant (IMT Manesar) including machinery (i) Rapid Sand Filter- 25 MLD (ii) Slow Sand Filter- 10 MLD	1 No.	17.00 Acre
4	M 15/16	Common Effluent Treatment Plant (i) 25 MLD (ii) 30 MLD	1 No. 1 No.	19.00 Acre 8.00 Acre

ARUN KUMAR GUPTA,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Town & Country Planning Department.